





# 'नवरत्न' से लिखा जाएगा विकास का नया अध्याय'



महानगर संचारदाता

## मददगार साबित होंगी नीतियां: दीयाकुमारी

जयपुरा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित एक समारोह में प्रदेश के सर्वांगीन विकास को गति प्रदान करने के लिए 9 नई नीतियों का अनावरण किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सम्बोधित करते हुए कहा कि ये नीतियां राजस्थान को देश का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। इसे न केवल निवेश आकर्षित होगा, बल्कि लाखों युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ये नीतियां हमारे राज्य के लिए रोडमैप होते हैं के साथ ही राजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में आने वाले निवेश की बढ़ाती का महत्वपूर्ण आधार भी है, जिनके माध्यम से राज्य में निवेश अनुकूल बातचारण तैयार करते हैं एवं प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दोगुना करने के लक्ष्य की प्रसिद्धि में मदद मिलेंगी। ये नई नीतियां नहीं बल्कि प्रदेश के लिए नीरोंसे संकर मन्ही हैं। हर एक नीति अपने आप में विकास का नया पैमाना ढाँचे वाली है। साथ ही हजारों लोगों को रोजगार मुहैया करवाने वाली हैं।



### प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा प्रदेश: बैरवा

उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि प्रदेश राजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से नवाचार एवं निवेश का महत्वपूर्ण केन्द्र बनाने उभर रहा है। निवेश अनुकूल नीतियों प्रदेश को प्रगति के पथ पर आगे ले जाने में मौल का पथर बनाने के लिए ये नीतियां मददगार साबित होंगी।

उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्द्धन राठौड़ ने कहा कि प्रदेश में नियंत्रित को बढ़ावा देने के लिए नियांत संवर्धन नीति लागू की जा रही है, जिसके माध्यम से नियंतियों की सहायता के लिए प्रावधान किए गए हैं। ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हीरालाल नायर ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विजय के अनुरूप प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में

एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति नीति 2024 का निर्माण किया गया है।

इस अवसर पर स्कूल शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, विकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गणेन्द्र सिंह खींचसर, जनजातीय क्षेत्र विकास मंत्री बबूलाल खाराड़ी, संसदीय कार्य मंत्री जोगार पटेल, जल संपादन मंत्री जोगार पटेल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोरायाम कुमावत, राजस्व मंत्री हेमंत शेषा, जन स्वास्थ्य अधिकारिकी मंत्री कन्हैया कन्हैयालाल, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा, नागरीय विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) झावर सिंह खर्चा, सार्वजनिक नियंत्रण राज्यमंत्री डॉ. मंजू बाबामार, उद्योग एवं वाणिज्य राज्यमंत्री के के. विश्वार्णी, गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेदम मौजूद रहे। साथ ही, मुख्य सचिव सुधांशु पांत, अध्यक्ष राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम शुभा सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव कर्जा आलोक, अतिरिक्त अध्यक्ष सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) शिखर अग्रवाल, अध्यक्ष राजस्थान राज्य भूद्वारा नियम संसदीप वर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास श्रेया गुहा, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह अननंद कुमार सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारीण तथा उद्योगपति एवं स्टेकहोल्डर्स उपस्थित रहे।

ये हैं 9 नई नीतियां, जिनका सीएम ने अनावरण किया है...

### 1 एमएसएमई नीति 2024 से मिलेगा लघु उद्योगों को बढ़ावा

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान एमएसएमई नीति-2024 प्रदेश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाएगी। इससे एमएसएमई को ऋण पर अतिरिक्त व्याज सहित बदला जाएगा, तकनीकी उन्नयन और गुणवत्ता प्रमाणन में सहायता मिल सकेगी।

### 4 हस्तशिल्प और एमएसएमई क्षेत्र को मिलेगा प्रोत्साहन

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कल्स्टर आयोजित विकास के जरूरि शिल्पकारों और लघु उद्योगों की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा। इसके एमएसएमई को ऋण पर अतिरिक्त व्याज सहित बदला जाएगा, तकनीकी उन्नयन और गुणवत्ता प्रमाणन में सहायता मिल सकेगी।

### 7 एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 से होगा हारित ऊर्जा का विस्तार

प्रदेश अक्षर ऊर्जा के उत्पादन में अग्रणी राज्य है और यहां सौर ऊर्जा और पवर ऊर्जा की असीमित सम्भालाएँ हैं। राज्य सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में 2 लाख 24 हजार करोड़ रुपये के एक्सप्रोजेक्ट के साथ ही, राजिंग राजस्थान प्री समिट में ऊर्जा के क्षेत्र में साथे छह लाख करोड़ रुपये से अधिक के विशेष समझौते बिले। प्रदेश में अक्षर ऊर्जा, बायोमास एवं वेस्ट टू एक्सो, ग्रीन हाइड्रोजन और ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा।

### 8 नवीन खनिज नीति 2024 में रोजगार और राजस्व वृद्धि का लक्ष्य

सीएम शर्मा ने कहा कि राजस्थान देश के प्रमुख खनिज उत्पादक राज्यों में से एक है। यहां 82 तरह के खनिजों के भूमिका हैं, जिनमें से 58 का व्यावसायिक स्तर पर खनन हो रहा है। वर्तीन नीति प्रोत्साहित करेगी। साथ ही, इस क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अटल इन्वेशन रस्ट्रियों और एक्सप्रोजेक्ट स्तर पर पहचान बना सकेंगे।

### 9 प्रदेश में एम-सेण्ट के उपयोग को मिलेगा बढ़ावा

मिर्मांग कार्यों में बढ़ावा के स्थान पर एम-सेण्ट के उत्पादक राज्यों में से एक है। यहां 82 तरह के खनिजों के भूमिका हैं, जिनमें से 58 का व्यावसायिक स्तर पर खनन हो रहा है। वर्तीन नीति प्रोत्साहित करेगी। साथ ही, इस क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक्टल इन्वेशन रस्ट्रियों और एक्सप्रोजेक्ट स्तर पर सहायता भी दिलायी जाएगी।

## भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राठौड़ की पीएम मोदी से मुलाकात



### राजिंग राजस्थान समेत अन्य विषयों पर हुई चर्चा

महानगर संचारदाता

जयपुरा भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने बुधवार को संसद भवन में नियंत्रित मुख्य सचिव कर्जा आलोक, अतिरिक्त अध्यक्ष सचिव ग्रामीण विकास श्रेया गुहा, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह अननंद कुमार सहित विभिन्न विभागों के विवरण दिया।

वहीं, दोनों के बीच राजिंग राजस्थान को लेकर चर्चा हुई। साथ ही राज्य सरकार के 1 वर्ष पूरा होने पर आयोजित कार्यक्रम पर भी चर्चा की गई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास राजस्थान के लिए विशेष रूप फोरेस करने के लिए नियंत्रित मुख्य सचिव कर्जा आलोक को आयोजित करते हुए विजय विशेष विभागों की आय वृद्धि में सहायता दिलायी।

### डेलीगेट्स को मिलेगा राजस्थानी त्यंजनों का स्वाद

- विदेशी निवेशकों को परोसे जाएंगे 50 से अधिक राजस्थानी त्यंजन
- राजिंग ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर त्यंजनों तेज

महानगर संचारदाता

जयपुरा शहर में आयोजित होने जा रही राजिंग ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में शामिल होने वाले 1 हजार विदेशी निवेशकों और 160 स्टेट गेस्ट 50 से अधिक राज्य के परापरिक व्यंजनों का स्वाद चर्चोंगे। इस समिट में मेहमानों को दाल-बाटी-चूरमा, गड्ढे की सब्जी, कर-सारणी, बाजरे की रोटी, मिर्ची बड़ा, लहसुन की चटनी और मालपुआ जैसे व्यंजन परोसे जाएंगे। इसके अलावा, स्थानीय मिटडायंस जैसे घेवर, फीजी और रब्बी भी मौजूद किया जाएगा। राज्य सरकार का फोरेस है कि विदेशी निवेशक न केवल यहां संभावनाओं को देखें, बल्कि यहां के खान-पान, संसारी और पर्यावरण को उठाएं। इसके अलावा भी यहां के महसूस करें।



### रसोई में पारंपरिक रौली का उपयोग

समिट के लिए खाना बनाने में राजस्थानी शैली का उपयोग होगा। रौली लकड़ी के चूड़े और परंपरागत बर्तनों में बनाए जाएंगे, ताकि उनकी वास्तविकता और प्रामाणिकता बरकरार रहे। राजस्थान की मसाहूर कच्ची घोड़ी, बालबेलिया वृक्ष और लोक संगीत के खान व्यंजनों का खाद्य समान बनाया जाएगा।

### विदेशी निवेशकों के लिए खास आयोजन

राजिंग ग्लोबल समिट में 160 से अधिक स्टेट गेस्ट और निवेशकों के उभयनाम हैं। इन में से एक खास आयोजन के लिए उत्पादक मेहमानों को केवल व्यंजनों का स्वाद ही नहीं, बल्कि उनक

# हाल ही 67वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सम्मेलन में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने सहित चार देशों की यात्रा करके लौटे हैं विधानसभा अध्यक्ष सदन की बैठक में अनुपस्थित रहने वाले विधायकों को लिखा व्यक्तिगत पत्र : देवनानी

मोहन लाल शर्मा

## महानगर साकार्त्तकार

जयपुर। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि प्रदेश की जनता की आवाज सदन में अधिक से अधिक रवां जाए, इसके लिए उन्होंने विधानसभा सदस्यों को सदन में अधिक से अधिक उपस्थित के लिए पत्र लिखा है। विधानसभा की कार्रवाई के दौरान कई सदस्यों की उपस्थित बहुत कम देखने को मिलती है, जिससे वे अपने क्षेत्र की बात सदन में नहीं उठा पाते हैं। विधानसभा अध्यक्ष के इस प्रयास से विधानसभा के आगामी नए सत्र की बैठकों में सदस्यों की उपस्थित निश्चित रूप से बढ़ेगी और विधायक अपने-अपने क्षेत्र की बात सदन में खेंगे।

करने सहित चार देशों की सफल यात्रा करके लौटे हैं। देवनानी ने इस दौरान ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडोनेशिया और सिंगापुर की संसदीय प्रणाली सहित वहां की संस्कृति सहित मिलन पक्षों को जाना है। राजस्थान विधानसभा की कार्रवाई ने सहित इन देशों की संसदीय प्रणाली पर वासुदेव देवनानी ने महानगर टाइम्स के साथ विशेष बातचीत की, जिसके प्रमुख अंश:-

### ■ विधानसभा सत्र की वर्ष 1990 तक पांच साल में 200 से 300 बैठकें होती रही हैं। अब 150 बैठकें भी नहीं होती हैं। नियमित सत्र और कार्रवाई की बैठक अधिक हो, इसके लिए क्या करें।

ये सही है विधानसभा सत्र की बैठकों में पहले के मुकाबले बहुत कमी आई है। 16वें विधानसभा के पहले ही साल में इसे 30 बैठकों तक किया गया है। अब

मेरा प्रयास रहेगा कि इसे किसी तरह 40 बैठकों तक ले कर जाया जाए। उन्होंने कहा कि पहली बार जीतकर आए विधायकों को भी वे अधिक से अधिक बैठने का अवसर देने का प्रयास करते हैं, जिससे उनके क्षेत्र की आवाज भी सदन में उठ सके।

### ■ एक साल का कार्यकाल पूरा होने तक जा रहा है। यह कार्यकाल कैसा रहा।

पहले ही साल में सदन में कई नवाचार



करते हुए सदन की गरिमा बढ़ाने में मैंने अपना योगदान दिया है। पहली बार सर्वतीर्थी बैठक बुलाई। लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों के साथ मेरे अच्छे संबंध रहे हैं। पक्ष-विपक्ष दोनों जो मुझ पर विश्वास किया, उस पर खरा उत्तरन का प्रयास किया है। कई बार सदन में अवरोध आया तो मैंने चैंबर में सदस्यों को बुलाकर समाधान निकाला। मेरा लक्ष्य है कि साल में तीन सत्र हों।

■ विधानसभा पेपर लैस होने जा रही है। जो विधायक टेक्नो-फ्रेंडली नहीं हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था की जाएगी इस सिस्टम के अन्ते के बाद।

करीब 15 करोड़ रुपए खर्च कर विधानसभा को हाईटैक बनाया जा रहा है। हर सीट पर आईपैड होगा और विधायक उसी से सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेंगे। नए साल में आयोजित होने तक रहने के बाद सत्र पूरी तरह से पेपरलैस होगा। इ-

विधान से विधानसभा सदन का विधानसभा सचिवालय को डिजिटल किए जाने वाले कार्य को 31 दिसंबर तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद विधायकों की ट्रेनिंग होगी। जब सत्र चलेगा तो जिस कार्यने ने यह प्रोजेक्ट लाया किया है, उसकी टीम भी सदन में मौजूद रहेगी। जैसे ही किसी विधायक को बीच सदन में कोई समस्या आएगी तो तलाक उसका समाधान किया जाएगा। इस टीम को भी सदन के कार्यदे-कानून सिखाए जाएंगे कि किसी तरह से चलते सदन में उन्हें सदस्यों की मदद करनी है। सहयोगी के रूप में एक वर्ष के लिए 25 लोग लगाए जाएंगे।

■ आप हाल ही चार देशों की यात्रा से लौटे हैं। उन देशों की संसदीय परंपराओं और विधायिका का अपने यहां से तुलनात्मक अध्ययन किस तरह करते हैं।

भारत का संविधान और लोकतंत्र सर्वश्रेष्ठ

है भारतीयों ने इन देशों में अपनी पहुंच बनाई है अपनी कर्मशीलता के दम पर। संसदीय परंपराएँ हमारे यहां ज्यादा अच्छी हैं। जापान की संसद में दोनों सदनों की स्थिति भारत जैसी है। हमारे यहां शूट्यूकल, प्रश्नकाल और खुले बहस होती है, वहां उन्होंने नहीं है। हालांकि वहां लोगों में अनुशासन बहुत ज्यादा है।

■ बांगलादेश में जिस तरह के हालात हुए हैं, ऐसे में वहां की संवैधानिक व्यवस्थाओं पर आप क्या कहेंगे।

बांगलादेश में हो रहा घटनाक्रम पीड़ियायक है। वहां अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। भारत में लोकतंत्र खतरे में है, वह केवल जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। उन्हें आसपास के राष्ट्रों में जाकर हालात देखने चाहिए। हमारे यहां के साथ गलत व्यवहार हो रहा है। उन्हें मारा जा रहा है। पांदिर तोड़े जा रहे हैं, जबकि भारत में अल्पसंख्यकों का समान होता है। कदम उठाने तोड़े जा रहे हैं। वहां कर्त्तव्यात्मक अध्ययन किया जाता है। जो हायां लिए संचयीय है। सरकार चिंतित है, लेकिन कर्त्तव्यात्मक काम किया जाता है।

राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती रद्द, स्वायत्त शासन विभाग ने जारी किया आदेश

महानगर संवाददाता

जयपुर। प्रदेश में 23,820 पदों पर होने वाली सफाई कर्मचारी भर्ती को रद्द कर दिया गया है।

इस संबंध में बुधवार को स्वायत्त शासन विभाग की ओर से 29 सिंतंत्र को जारी भर्ती विजिति को वापस लेने के अंदेशा जारी किए गए। यह तीव्री वार है जब इस भर्ती को रोका गया है। उल्लेखनीय है कि हाल ही संयुक्त वाल्मीकी एवं सफाई श्रमिक संघ और प्रशासन के बीच अनुभव प्रमाण पर नहीं बनने के कारण जयपुर के हेरिटेज और ग्रेटर नगर निगम में सफाई कर्मचारियों की भर्ती स्थगित करने का समझौता हुआ था।

**लगातार मिल रही ही शिकायतें**

विभान नगरी निकायों से फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बनाए जाने की शिकायतें लगातार आ रही थीं। इसके बाद विवाद हो गया। यह तीव्री वार है जब इस भर्ती को रोका गया है। उल्लेखनीय है कि हाल ही संयुक्त वाल्मीकी एवं सफाई श्रमिक संघ और प्रशासन के बीच अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बनने के कारण जयपुर के हेरिटेज और ग्रेटर नगर निगम में सफाई कर्मचारियों की भर्ती स्थगित करने का समझौता हुआ था।

**उपजागरण पत्र**

कर्मचारी ने लगातार मिल रही ही शिकायतें के साथ अध्ययन किया जाए।

सरकार को बिना रोका गया है। इस भर्ती को रोका गया है। इस भर्ती की विवादिति को बिना रोका गया है।

कर्मचारी ने अपनी विवादिति को बिना रोका गया है।

कर्मचारी ने अपनी विवादिति को बिना रोका गया है।

कर्मचारी ने अपनी विवादिति को बिना रोका गया है।

कर्मचारी ने अपनी विवादिति को बिना रोका गया है।

कर्मचारी ने अपनी विवादिति को बिना रोका गया है।

कर्मचारी ने अपनी विवादिति को बिना रोका गया है।

कर्मचारी ने अपनी विवादिति को बिना रोका गया है।

कर्मचारी ने अपनी विवादिति को बिना रोका गया है।

कर्मचारी ने अपनी विवादिति को बिना रोका गया है।

कर्मचारी ने अपनी विवादिति को बिना रोका गया है।

कर्मचारी ने अपनी विवादिति को बिना रोका गया है।

कर्मचारी ने अपनी विवादिति को बिना रोका गया है।

कर्मचारी ने अपनी विवादिति को बिना रोका गया है।

कर्मचारी ने अपनी विवादिति को बिना रोका गया है।

कर्मचारी ने अपनी विवादिति को बिना रोका गया है।

कर्मचारी ने अपनी विवादिति को बिना रोका गया है।

कर्मचारी ने अपनी विवादिति को बिना रोका गया है।

कर्मचारी ने अपनी विवादिति को बिना रोका गया है।

कर्मचारी ने अपनी विवादिति को बिना रोका गया है।

कर्मचारी ने अपनी विवादिति को बिना रोका गया है।

कर्मचारी ने अपनी विवादिति को बिना रोका गया है।

कर्मचारी ने अपनी विवादिति को बिना











सीएम हिमंत बिहारी सरमा ने गौमांस के उपभोग पर मौजूदा कानूनों में संशोधन को दी मंजूरी, मंत्री बोले- कांग्रेस फैसले का खागत करे या पाकिस्तान जाए

# असम में होटल, रेस्टोरेंट और सार्वजनिक कार्यक्रमों में गौमांस पूर्ण प्रतिबंध

महानगर संवाददाता



गुवाहाटी। असम सरकार ने बुधवार को रेस्टरां, होटल, सार्वजनिक समारोहों और अन्य सामुदायिक स्थानों पर गौमांस परोसने और खाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री हिमंत बिहारी सरमा ने कहा कि राज्य कैबिनेट की बैठक में गौमांस के उपभोग पर मौजूदा कानूनों में संशोधन को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद सरमा ने कहा कि असम में हमने फैसला किया है कि किसी भी रेस्टरां या होटल में गौमांस नहीं परोसा जाएगा और न ही किसी सार्वजनिक समारोह या सार्वजनिक स्थान पर इसकी अनुमति दी जाएगी। सीएम हिमंत बिहारी सरमा ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। सीएम ने बताया कि वह फैसला मत्रिमंडल था। 23 नवंबर को रिजल्ट आने के बाद कांग्रेस की बैठक में लिया गया है। अब राज्य के होटलों, रेस्टोरेंट्स और सार्वजनिक स्थानों पर गौमांस नहीं परोसा जा सकता।

राज्य में गौमांस प्रतिबंध की घोषणा करते हुए जल संसाधन मंत्री पीयूष हजारिका ने कहा कि कांग्रेस इस फैसले का स्वागत करें या पाकिस्तान जाए। दरअसल, सामग्री सीट पर उच्चनाव के लिए 13 नवंबर को मतदान हुआ था। 23 नवंबर को रिजल्ट आने के बाद कांग्रेस की हार पर सांसद रकीबुल हुसैन ने भाजपा पर बीफ बांटने का आरोप लगाया था।

इसके जबवाब में सीएम हिमंत बिहारी सरमा ने बुधवार की बैठक के बाद मीडिया से कहा कि वे राज्य में गौमांस पर प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार हैं, बसर्ते कांग्रेस इसे लिखित में दें। **पहले मर्दियों के पास गौमांस खाने पर रोक थी अब पूरे राज्य में बैन**

सीएम सरमा ने कहा कि पहले मर्दियों के पास

गौमांस खाने पर रोक थी, लेकिन अब हमने इसे पूरे राज्य में लागू कर दिया है। आप इसे किसी भी सामुदायिक या सार्वजनिक स्थान, होटल या रेस्टरां में नहीं खा पाएंगे। सीएम सरमा ने इस बात पर जो दिया कि नया प्रावधान राज्य में मवेशी हत्या रोकने के सरकार के उद्देश्य के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भूपेन बोरा और रकीबुल हुसैन जो चाहते थे, वह

अब पूरा होगा। इसलिए हमें उम्मीद है कि कांग्रेस इस फैसले में हमारा समर्थन करेगी।

**वेद्य मतदाताओं को गौमांस देकर चुनाव जीत सकते हैं**

सीएम सरमा ने पूछा था कि क्या गौमांस सामग्री सीट जीती जा सकती है। सरमा ने कहा था कि जिनमें मैं जानना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस मतदाताओं को गौमांस देकर सामग्री जीत रही थी। वह सामग्री को अच्छी तरह से जानते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि गौमांस देकर सामग्री जीती जा सकती है। इस साल धुबरी लोकसभा सीट से 10.12 लाख से अधिक मतों के रिकॉर्ड अंतर से जीतकर हुसैन सांसद बने हैं। इससे पहले वे लातार पांच बार सामग्री से विधायक रहे थे।

**'हिंदू मुस्लिम-ईसाई सभी खाना बंद करें गौमांस'**

सीएम सरमा ने कहा कि मैं रकीबुल हुसैन से प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार हूं।

कहाना चाहता हूं कि गौमांस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, व्यक्ति उन्हें खुद कहा है कि वे गलत हैं। उन्हें मृज़े के बताने लिखित में देने की जरूरत है। भाजपा और कांग्रेस को गौमांस के बारे में नहीं बालना चाहिए। बीजेपी, सीपीएम कोई भी ऑफर नहीं कर पाएगी और हिंदू, मुस्लिम और ईसाई सभी को गौमांस खाना बंद कर देना चाहिए।

**क्या कहता है असम मवेशी संक्षण अधिनियम**

असम में गौमांस का सेवन गैरकानूनी नहीं है, लेकिन असम मवेशी संक्षण अधिनियम 2021 तक क्षेत्रों में मवेशी वध और गौमांस की विक्री पर प्रतिबंध लगाया है, जहां हिंदू, जैन और सिख बहुमतांक हैं और किसी मोर्दर या वैष्णव मठ के पांच किलोमीटर के दौरान में हैं। बीते दिनों सीएम सरमा ने कहा था कि अगर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन बोरा और रकीबुल हुसैन जो चाहते थे, वह

## मुश्किल में फंसी कर्नाटक सरकार का बड़ा कदम मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण के तहत दी गई 48 जमीनों का आवंटन रद्द

महानगर संवाददाता

बंगलूरु। कर्नाटक में इन दिनों जमीन घोटाले का मुद्रा छाया हुआ है। मूडा और वार्षिकी कौरपोरेशन घोटाले को लेकर सिद्धारमेया सरकार विषय पर निशाने पर रहा। अब कर्नाटक सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। उसने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडी) द्वारा आवंटित 48 भूखंडों को पिछले साल 23 मार्च को एक प्रस्ताव द्वारा आवंटित किया गया। इन भूखंडों को विवादित 50:50 अनुपात योजना के तहत आवंटित नहीं किया गया था, जिसकी जांच लोकायुक्त के साथ-साथ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा भी की जा रही है।

आरोप है कि मूख्यमंत्री सिद्धारमेया की पली पार्टी के बीएम को भी मौरु के प्रमुख इलाके में एमयूडी द्वारा किए गए आवंटन से 14 भूखंड का लाभ प्राप्त हुआ। शहरी विकास प्राप्ति भालाकी उहाने आवंटन रद्द किया गया है। शहरी विकास का मूडा प्रस्ताव रद्द करने का आदेश इस साल आठ अप्रैल को मूडा के तत्कालीन आवंटित को रेडी, जो मूडा के अध्यक्ष भी है, उहाने आवंटन रद्द किया गया है। आदेश में तत्कालीन आवंटित के जवाब को भी खारिज किया गया था। भाजपा का कहना है कि नेशंश राज्यालय के बांधनों में वास्तविक विवाद है। भाजपा ने बालाकी का एक ऑफियोलोजी ने बालाकी के बांधनों में वास्तविक विवाद किया गया है। आदेश में वास्तविक विवाद के बांधनों में वास्तविक विवाद किया गया है।

**बालाकी विवाद का आवंटन रद्द किया गया**

महानगर संवाददाता

जाएगा। उहाने बताया कि इन भूखंडों को विवादित 50:50 अनुपात योजना के तहत आवंटित नहीं किया गया था, जिसकी जांच लोकायुक्त के साथ-साथ विवादित निदेशालय द्वारा भी की जा रही है। उहाने बताया कि इन भूखंडों को एमयूडी द्वारा किए गए आवंटन से 14 भूखंड का लाभ प्राप्त हुआ। शहरी विकास का मूडा प्रस्ताव रद्द करने का आदेश इस साल आठ अप्रैल को मूडा के तत्कालीन आवंटित को रेडी, जो मूडा के अध्यक्ष भी है, उहाने आवंटन रद्द किया गया है। आदेश में तत्कालीन आवंटित के जवाब को भी खारिज किया गया है। भाजपा का कहना है कि नेशंश राज्यालय के बांधनों में वास्तविक विवाद है। भाजपा ने बालाकी का एक ऑफियोलोजी ने बालाकी के बांधनों में वास्तविक विवाद किया गया है। आदेश में वास्तविक विवाद के बांधनों में वास्तविक विवाद किया गया है।

**बालाकी विवाद का आवंटन रद्द किया गया**

महानगर संवाददाता

नई दिल्ली। किसानों व उनकी फसल के लिए न्यूतनम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का मुद्रा बुधवार को राज्यसभा में उठाया गया। विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा के अन्य सभी कार्यों को खारिज किया गया। बालाकी उहाने आवंटन रद्द किया गया है। उहाने बताया कि विवादित 50:50 अनुपात योजना के तहत आवंटित नहीं किया गया था, जिसकी जांच लोकायुक्त के साथ-साथ विवादित निदेशालय द्वारा भी की जा रही है। उहाने बताया कि इन भूखंडों को एमयूडी द्वारा किए गए आवंटन से 14 भूखंड का लाभ प्राप्त हुआ। शहरी विकास का मूडा प्रस्ताव रद्द करने का आदेश इस साल आठ अप्रैल को मूडा के तत्कालीन आवंटित को रेडी, जो मूडा के अध्यक्ष भी है, उहाने आवंटन रद्द किया गया है। आदेश में तत्कालीन आवंटित के जवाब को भी खारिज किया गया है। भाजपा का कहना है कि नेशंश राज्यालय के बांधनों में वास्तविक विवाद है। भाजपा ने बालाकी का एक ऑफियोलोजी ने बालाकी के बांधनों में वास्तविक विवाद किया गया है। आदेश में वास्तविक विवाद के बांधनों में वास्तविक विवाद किया गया है।

**बालाकी विवाद का आवंटन रद्द किया गया**

महानगर संवाददाता

चल रही है। किसानों से न्यूतनम समर्थन मूल्य का जो बादा किया गया था, वह बादा नहीं नियमानुसार जारी किया गया। बालाकी उहाने आवंटन रद्द किया गया है। उहाने बताया कि विवादित 50:50 अनुपात योजना के तहत आवंटित नहीं किया गया था, जिसकी जांच लोकायुक्त के साथ-साथ विवादित निदेशालय द्वारा भी की जा रही है। उहाने बताया कि इन भूखंडों को एमयूडी द्वारा किए गए आवंटन से 14 भूखंड का लाभ प्राप्त हुआ। शहरी विकास का मूडा प्रस्ताव रद्द करने क

## आईपीएल की ब्रांड वैल्यू 1 लाख करोड़ और चार टीमों की पहली बार 100 मिलियन डॉलर पार

# टीमों में चेन्नई सुपर किंग्स की वैल्यू सबसे ज्यादा, 1,033 करोड़ पहुंची

महानगर संवाददाता

यह जानकारी दी गई है।

2023 में पहली बार आईपीएल की टोटल ब्रांड वैल्यू 10 बिलियन डॉलर के पार गई थी। पिछले साल यह 10.7 बिलियन डॉलर (90,679 करोड़ रुपए) रही थी। वहाँ 2009 में वैल्यूशन 2 बिलियन डॉलर यानी 1.01 लाख करोड़ रुपए पहुंच गई है। ब्रांड वैल्यूशन करने वाली कंपनी ब्रांड फाइनेंस की नई रिपोर्ट में

यह भी बताया गया है कि आईपीएल की चार टीमों-चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस, रोयल चैलेंजर्स बैंगलुरु और कोलकाता नाइट रायडर्स की ब्रांड वैल्यू भी पहली बार 100 मिलियन डॉलर (847 करोड़ रुपए) से ज्यादा हो गई है।

वहाँ

2008 में शुरू हुई थी। इंडियन प्रीमियर लीग साल 2009 में वैल्यूशन 2 बिलियन डॉलर (847 करोड़ रुपए) से ज्यादा हो गई है।

### आईपीएल की 10 टीमों में सीएसके की ब्रांड वैल्यू सबसे ज्यादा

आईपीएल की 10 टीमों में सीएसके की ब्रांड वैल्यू सबसे ज्यादा है। चेन्नई की ब्रांड 52 फीसदी बढ़कर 1,033 करोड़ रुपए हो गई है। वहाँ ब्रांड वैल्यू के साथ भी मैं मुंबई दूसरे बंदर पर है, इसकी वैल्यूशन 36 फीसदी बढ़कर 1,008 करोड़ रुपए पहुंच गई है। आरसीबी 991 करोड़ रुपए (+67 फीसदी) की ब्रांड वैल्यू के साथ तीसरे बंदर पर है। वहाँ के आरके 923 करोड़ रुपए (+38 फीसदी) की ब्रांड वैल्यू के साथ तीसरे बंदर पर है।

ब्रांड वैल्यू 30 फीसदी, दिल्ली किंग्स की 49 फीसदी और

फाइनेंस की 24 फीसदी, जंजाब लखनऊ सुपर जायंट्स की 29

वैल्यू के साथ चौथे बंदर पर है। इस रिपोर्ट में एसआरएच पांचवें बंदर पर है। लखनऊ ईंटरडाक ब्रांड वैल्यू में सबसे ज्यादा गोथ : सभी टीमों में सनराइजर्स हैंदरबाद की ब्रांड वैल्यू में सबसे ज्यादा गोथ है। टीम की वैल्यूशन 76 फीसदी बढ़कर 719 करोड़ रुपए हो गई है। यह लीग के बढ़ते ईंटरनेशनल इंडियान्स और फाइनेंशियल अधीक्षितों को दर्शाता है।

टीमों की ब्रांड वैल्यू सबसे कम 5 फीसदी ही बढ़ी है। ब्रांड फाइनेंस के मुताबिक, टॉप-5 आईपीएल टीमों में एकसंपेशन यानी विस्तार की काफी संभावनाएं हैं। इन टीमों में पॉयलर फुटबॉल लीग, लीग-इंग्लिश प्रीमियर लीग, ला लीगा, बुडेसलीगा, सीरी ए और लीग-1 की टॉप 5 टीमों के लेवल तक अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ाने की क्षमता है।

टॉप-5 आईपीएल टीमों की कंबाइन ब्रांड वैल्यू 4,667 करोड़ रुपए : टॉप-5 आईपीएल टीमों की कंबाइन ब्रांड वैल्यू 551 मिलियन डॉलर यानी 4,667 करोड़ रुपए है, यह फुटबॉल लीग की तुलना में काफी कम है। बुडेसलीगा की टॉप 5 टीमों की कंबाइन ब्रांड वैल्यू 2.9 बिलियन डॉलर यानी 24,566 करोड़ रुपए है।

## सेंसेक्स 110 अंक चढ़कर 80,956 पर बंद

महानगर संवाददाता

मुंबई। सेंसेक्स 4 दिसंबर को 110 अंक के बढ़त के साथ 80,956 पर बंद हुआ। निपटी में भी 10 अंक की बढ़त रही, ये 24,467 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स 30 शेर्यों में से 15 में गिरावट और 15 में जीएच तेजी देखने को मिली है।

निपटी के 50 शेर्यों में से 30 में गिरावट और 20 में तेजी देखने को मिली है। एनएसई के सेक्टरेल इंडेक्स में पीएसयू बैंकिंग और रियलटी में 2 फीसदी से ज्यादा की तेजी रही। एचडॉएफसी लाइफ 2.597 की बढ़त के साथ निपटी का टॉप गेमर रहा। वहाँ एयरटेल 2.33त की गिरावट के साथ टॉप लूजर रहा।

### स्थिगी का शेयर 3.04

#### फीसदी चढ़ा

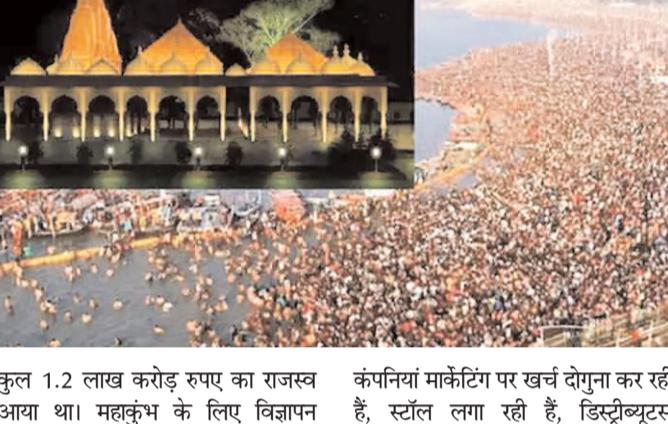
बेहतर तिमाही नतीजे आने के बाद ऑनलाइन फूट डिल्लीवारी प्लेटफॉर्म रिपोर्ट के शेर्य में 15.25 रुपए (3.04 फीसदी) की बढ़त रही रही। एचडॉएफसी लाइफ 2.597 की बढ़त के साथ निपटी का टॉप गेमर रहा। वहाँ एयरटेल 2.33त की गिरावट के साथ टॉप लूजर रहा।

क्षणी का शेयर 3.04

# महाकुंभ में 3,000 करोड़ रुपए खर्च करने की तैयारी में कंपनियां

### प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हो रहा है महाकुंभ

महानगर संवाददाता



नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। 45 दिनों तक चलने वाले इस महाकुंभ में ब्राह्मि और मार्केटिंग पर भारतीय उद्योग जात कम से कम 3,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रहा है। कंपनियों को हर 12 साल में आयोजित होने वाले इस महाकुंभ में भी भारी खपत का अवसर दिख रहा है। यह 13 जनवरी से शुरू हो रहा है और इसमें 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उमीद है।

दिनुस्तान यूनिविवर, कोका-कोला, आईटीसी, बिसलेरी, पारले, डाकर, पेटीएम और इमारी के साथ-साथ मोबिलिटी लैल्यूस और इंवी कंपनियों ने भी इसमें रुचि दिखाई है। सीओआईआई की एक पिछली रिपोर्ट के अनुसार, 2013 में हुए पिछले महाकुंभ ने हवाई अड्डों पर होटलों के ब्रांड वैल्यूओं के अनुसार, आज तक 12,000 करोड़ रुपए का रेस्टॉरेंट लूजर रुम्हन किया था, जबकि 2019 के कुंभ मेले ने

कुल 1.2 लाख करोड़ रुपए का राजस्व आया था। महाकुंभ के लिए विज्ञापन अधिकार विसिल करने वाली क्रेन्स्स एडवराइजिंग के बाइस प्रेजिडेंट राज मोहंठी ने कहा, हमारे फोन पर लगातार घेरते हैं और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सवाल आ रहे हैं। एकएमसीजी, फार्मा, लो-कॉस्ट मोबिलिटी प्रोवाइडर, इंवी और यूपीआई गेटवे की ओर से इसमें भारी रुचि दिखाई है। यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम है, इसलिए ब्रांड अधिकतम लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। कार्यक्रम के आयोजक एक अधिकारी ने बताया कि कंपनियों मार्केटिंग पर खर्च दोगुना कर रही है, स्टॉल लगा रही है, डिस्ट्रीब्यूरस नियुक्त कर रही है और सलाइ चेन तैयार कर रही है, और अध्यात्मिक पैक लॉन्च कर रही हैं और यहाँ तक कि इंस्ट्राम जैसे सोशल प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल कर रही है। नियमित स्टॉल के अलावा इटरैक्टर वृथ, वर्नुअल रियलिटी एक्स्परियंस जैसे ब्रांड लाऊं और एपीजैमेंट टचपॉइंट भी हैं। डाकर ने कहा कि वह उपभोक्ता संपर्क बढ़ाने के तरीकों पर काम कर रही है। डाकर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी

कंपनियों मार्केटिंग पर खर्च दोगुना कर रही है, स्टॉल लगा रही है, डिस्ट्रीब्यूरस के लिए कंज्मूर एक्विवेशन की एक सीरीज बनाई है। कंपनी कुंभ परिसर के अंदर स्वचालित ट्रॉफेरेंट डिपैसर के साथ दंत स्तान जॉन स्पायिट कर रही है। इसके आयोजन में लॉजिस्टिक्स की चुनौतियों से निपटने के लिए योजनाएं बना रही हैं। पार्किंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर एक और पॉयेसेटेड पार्किंग सॉल्यूशन प्रदान करने के लिए आगे आई है। इसी तरह पर्यावणण के अनुकूल परिवहन विकल्पों के लिए आगे आई है। इसी तरह पर्यावणण के अनुकूल परिवहन विकल्पों के लिए आगे आई है। इसी तरह पर्यावणण के अनुकूल परिवहन विकल्पों के लिए आगे आई है।

### पार्किंग की व्यवस्था

मंगलरेत्री धूप, बिंगो चिप्स और यिणी नूडल्स सहित आईटीसी के ब्रांड भी कुंभ के लिए वियोगकर्ताओं के साथ संपर्क को मजबूत करने के लिए कंज्मूर एक्विवेशन की एक सीरीज बनाई है। कंपनी कुंभ परिसर के अंदर स्वचालित ट्रॉफेरेंट डिपैसर के साथ दंत स्तान जॉन स्पायिट कर रही है। इसके आयोजन में लॉजिस्टिक्स की चुनौतियों से निपटने के लिए योजनाएं बना रही हैं। पार्किंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर एक और पॉयेसेटेड पार्किंग सॉल्यूशन प्रदान करने के लिए आगे आई है। इसी तरह पर्यावणण के अनुकूल परिवहन विकल्पों के लिए एक और पॉयेसेटेड पार्किंग सॉल्यूशन प्रदान करने के लिए आगे आई है।

## अधिक स्वास्थ्यकारक है बहु-स्रोत खाद्य तेल

महानगर संवाददाता

सफोला टोटल भी चुन सकते हैं। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने के लिए एकल-स्रोत तेलों की तुलना में इन दोनों तरों का मिश्रण अधिक प्रभावी होता है।

कुछ बहु-स्रोत खाद्य तेल का उपयोग अम लोगों की पहली पसंद है, क्योंकि उनका मानना है कि, एकल-बीज परिष्कृत तेल की तुलना में बहु-स्रोत खाद्य तेल का उपयोग अम लोगों की पहली पसंद है, क्योंकि उनका मानना है कि, एकल-बीज परिष्कृत तेल की तुलना में बहु-स्रोत खाद्य तेल का





